Permission to Consolidated Seafood Corporation, U.S.A.

1789. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether Government have granted permission to a UN firm named Consolidated Seafood Corporation, USA for a Rs. 598 crore deep sea fishing project;

(b) the details of this proposals; and

(c) whether there is any Indian collaborator in the said project ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) : (a) to (c) Government have given permission to M/s Indfish Ltd., New Delhi to undertake deep sea fishing project in collaboration with M/s. Consolidated Sea Food Corporation, USA. The equity participation in the project between Indian and U.S. Company would be 60 : 40 respectively. The Joint Venture Company would acquire 12 Multi Liners, 48 Mini Liners and 2 Tenders (Service Vessels) for operation in Indian Exclusive Economic Zone and beyond to exploit Tuna and Tuna like resources etc. The project envisages annual catch of 40,000 Metric Tons of fish to earn foreign exchange of Rs. 546 crores.

Applications cleared under charter fishing policy, 1989

1790. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state the status of the applications made by technocrats and small entrepreneurs for chartering under the 1989 scheme of charter fishing ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) : Under the 1989 charter policy announced by the Government a total number of 175 applications were received for grant of letter of intent for chartering foreign fishing vessels. No letter of intent/charter permit has been granted to any of these applicants as the 1989 charter policy has not been operationalised.

सब्जियों के उत्तम उपयोग की योजना

1791. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सब्जियों की बर्बादी को रोकने के लिए उनका सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करने हेतु क्या-क्या योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) ऐसी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना-कितना लक्ष्य रखा गया और इन वर्षों में वर्षवार क्या उपलब्धि रही ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) यद्यपि राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं फिर भी इस मंत्रालय ने फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विकास के लिए सरकारी सेक्टर, संयुक्त सेक्टर, सहकारी सेक्टर यूनिटों आदि को सहायता देने हेतु आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के उद्देश्य से विभिन्न योजना स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों और वर्ष 1992-93 में प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

योजना स्कीम का नाम	वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित निधि (करोड़ रुपयों में)
1	2
1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य और प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए स्कीम ।	1,50